

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15366/2024

गनराज बिश्रोई पुत्र केसराराम बिश्रोई, उम्र लगभग 39 वर्ष, ढोलिया, जैसलमेर (राज.)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, मार्फत निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर (राज.)।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सरकारी जिला अस्पताल, पोकरण, जिला जैसलमेर।

----प्रतिवादीगण

संलग्न**याचिकाओं का समूह [अनुलग्नक 'ए'] के अनुसार****याचिकाकर्ता(गण) की ओर से:**

श्री मनीष पटेल, श्री मुकेश राजपुरोहित के साथ सुश्री अदिति शर्मा, श्री कैलाश जांगिड़, श्री एस.के. पूनिया, श्री सुरेश कुमार बिश्रोई, श्री आर.डी. मीणा, श्री हरीश पुरोहित, श्री राकेश जाखड़, श्री अंकुर माथुर के साथ सुश्री दिव्या बापना, श्री सुनील पुरोहित, श्री मनीष पटेल, श्री संजय राज पंडित, श्री रवींद्र सिंह चंपावत, श्री विक्रम सिंह राठौड़, श्री लोकेश माथुर, श्री सुरेश खडाव, श्री हेमंत सिंह सोलंकी, श्री प्रियंक कवालिया, श्री मनोज चौधरी, श्री सी.एस. कोटवानी, श्री हर्षित भुरानी के साथ सुश्री हेली पाठक और श्री महिपाल राठौर, श्री आर.एस. चौधरी, श्री यशपाल खिलेरी, श्री मनजीत, श्री हिमांशु चौधरी, श्री मुकेश व्यास, श्री जे.एस. भालेरिया, श्री रिपुदमन सिंह, श्री विकास बिजारनिया, श्री सुरेश चारण, श्री एन.आर. चौधरी, श्री देवेन्द्र सांवलोट, श्री विक्रम शर्मा, श्री राहुल व्यास, श्री कनिष्क सिंघवी, श्री गोविंद लाल, श्री वी.एस. भावला, श्री दिनेश ओझा, श्री अनिल बिदान हालू, श्री आर.के. सैनी, श्री के.आर. सहारण, श्री अर्जुन सिंह, श्री उस्मान गनी, श्री पुनीत सिंघवी, श्री पवन सिंह, श्री सिकंदर खान, श्री सरंज विज, श्री देवेश ए. पुरोहित, श्री रमेश कुमार।

प्रतिवादी(गण) की ओर से:

श्री नरेंद्र सिंह राजपुरोहित, एएजी के साथ श्री यशराज सिंह कानावत, श्री महावीर विश्वाई, एएजी, श्री वैभव बांग बनाम श्री एन.के. मेहता, उप महाधिवक्ता (Dy.G.C.), श्री कुलदीप वैष्णव, उप महाधिवक्ता के साथ श्री दीपक वैष्णव, सुश्री डॉली जायसवाल बनाम श्री महेंद्र विश्वाई, श्री समीर श्रीमाली, एजीसी, श्री ललित पारीक, श्री ललित परिहार, श्री दिग्विजय सिंह सोढा, श्री जे.के. मिश्रा, श्री अखिलेश राजपुरोहित, श्री सुरेंद्र सिंह चौधरी, श्री रितु राज सिंह भाटी, श्री आई.आर. चौधरी, एएजी, श्री एस.आर. पालीवाल, जी.सी.

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा**निर्णय****17/02/2025**

1. इस सामान्य आदेश के माध्यम से, अनुलग्नक 'ए' में सूचीबद्ध याचिकाओं के पूरे समूह का निपटारा किया जा रहा है क्योंकि उनमें एक ही विवाद शामिल है।
 2. यहाँ याचिकाकर्तागण, जो विभिन्न विभागों में सेवारत हैं, संबंधित आदेशों को चुनौती दे रहे हैं जिसके तहत उनकी सेवाओं को एक श्रेणी में रखा गया है, जिसे 'पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा' (Awaiting Posting Orders - APO) कहा जाता है। यहाँ विवाद के निर्णय के लिए मामलों के व्यक्तिगत तथ्य प्रासंगिक नहीं हैं, क्योंकि इस न्यायालय को प्रतिवादीगण द्वारा पारित चुनौतीपूर्ण आदेशों (APO) की वैधता के साथ-साथ कथित प्रशासनिक अनुचितता पर फैसला करना है।
 3. याचिकाकर्ताओं की सामान्य शिकायत यह है कि संबंधित चुनौती दिए गए स्थानान्तरण आदेशों/APO के कारण, अचानक से, बिना कोई कारण बताए/सूचित किए उनसे काम वापस ले लिया गया है या यदि/जहाँ सूचित किया गया है, तो वे मान्य नहीं हैं। इसके अलावा, उन्हें APO बनाने की आड़ में, उन्हें उनके कार्यस्थल पर अपमानित किया जा रहा है।
 4. इस बिंदु पर, प्रतिवादीगण द्वारा शीर्षक वाली रिट याचिका संख्या 15366/2024 (याचिकाकर्ता एक नर्सिंग अधिकारी है) में दायर किए गए उनके जवाब के रुख पर ध्यान देना उचित होगा, जिसे व्यापक होने के कारण सभी याचिकाओं के संबंध में कानून पर आधारित बचाव माना जा सकता है। इसका प्रासंगिक अंश निम्नलिखित है:
-

"1. यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता दिनांक 03.09.2024 के आदेश और दिनांक 06.09.2024 के आदेश के विरुद्ध है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही के कारण और याचिकाकर्ता के खिलाफ एक प्राथमिक जांच लंबित होने के कारण पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में रखा गया था।

2. याचिकाकर्ता संतोषजनक रूप से और उत्तरदाता प्रत्यर्थी अधिकारियों की संतुष्टि के अनुसार काम नहीं कर रहा है। इसलिए, जनहित में और प्रशासनिक कारणों से, याचिकाकर्ता को पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में रखा गया है। उत्तर प्रत्यर्थियों द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत, उचित और वैध है, जिसे कानून के अनुसार और राज्य सरकार में निहित शक्तियों के अनुसार पारित किया गया था। इसलिए, यह पोषणीय है, और पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

3. याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार द्वारा पारित विवेकाधीन आदेश को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने राजस्थान सेवा नियम, 1958 (इसके बाद 1958 के नियम) के नियम 25-ए को आधार बनाया है। 1958 के नियमों का नियम 25-ए पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा की अवधि के दौरान वेतन के बारे में प्रावधान करता है। नियम 25-ए में कोई मार्गदर्शक सिद्धांत उल्लिखित नहीं हैं जो यह प्रदान करते हैं कि पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा केवल कुछ स्थितियों और परिस्थितियों में ही की जाती है। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि 1958 के नियमों के नियम 25-ए के तहत उल्लिखित राजस्थान सरकार के निर्णय का आधार क्षेत्र को नियंत्रित करता है, लेकिन उसमें उल्लिखित शब्द 'आमतौर पर' यह प्रदान करता है कि उल्लिखित शर्तें उदाहरणात्मक हैं न कि संपूर्ण। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा राजस्थान सरकार के फैसलों पर रखा गया भरोसा टिकाऊ नहीं है, और राज्य सरकार के पास जनहित में जब भी आवश्यक हो, पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा के आदेश पारित करने का अधिकार है। सरकारी आदेशों में उल्लिखित उदाहरणात्मक शर्तें संपूर्ण नहीं हैं, और इसलिए, उन्हें एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता है जिसके तहत पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा के आदेश जारी किए जा सकते हैं। याचिकाकर्ता राज्य सरकार का एक कर्मचारी है जिसे राज्य सरकार के निर्देशों और पर्यवेक्षण के अनुसार काम करना है। राज्य सरकार के पास कर्मचारियों को पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा के तहत रखने का अधिकार है जब यह जनहित में और प्रशासनिक आवश्यकता के कारण आवश्यक हो। इस मामले में, जनहित की आवश्यकता थी कि याचिकाकर्ता को वर्तमान पदस्थापन पर जारी नहीं रखा जाना चाहिए और उसे पोकरण में नर्सिंग अधिकारी के रूप में जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए, उत्तरदाता प्रत्यर्थियों द्वारा दिनांक 21.06.2024 को आदेश पारित किया गया था, और यह राज्य सरकार के क्षेत्र और अधिकार के अनुसार है, और यह पोषणीय है।

4. स्थानांतरण और पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा का अधिकार पूरी तरह से राज्य सरकार के क्षेत्रके भीतर आता है। राज्य सरकार व्यापक जनहित में एक विशेष स्थान पर सरकारी कर्मचारी की सेवाओं का उपयोग करने के लिए अधिकृत है, और इसलिए, प्रशासनिक आवश्यकता में, वर्तमान मामले में दिनांक 06.09.2024 को आदेश पारित किया गया था, और यह पूरी तरह से उचित और कानून के अनुसार है। माननीय खंडपीठ ने डीबी विशेष अपील रिट संख्या 733/2022, पुष्कर लाल माली के मामले में, 24.11.2022 को तय किया था कि जहाँ किसी व्यक्ति के खिलाफ जांच शुरू की गई थी, वहाँ एक व्यक्ति को APO पर रखना वैध है। इसलिए, इसे बनाए रखने योग्य है, और रिट याचिका, गुण-दोष से रहित होने के कारण, खारिज किए जाने योग्य है।"

5. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता एकमत से तर्क देते हैं कि याचिकाकर्ताओं को, उनके सराहनीय सेवा रिकॉर्ड के बावजूद, अप्रत्याशित रूप से पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा के तहत रखा गया है। आदेश जल्दबाजी में या तो राजनीतिक हस्तक्षेप या अन्य दुर्भावनापूर्ण कारणों से और बिना उचित विचार के जारी किए गए हैं।

5.1. यह प्रस्तुत किया जाता है कि चुनौती दिए गए स्थानांतरण/APO आदेश राजस्थान सेवा नियम, 1951 (RSR) के नियम 25-ए के प्रावधानों के प्रतिकूल हैं, जो उन परिस्थितियों को निर्धारित करता है जिनके तहत एक राज्य सरकारी सेवक को पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा के तहत रखा जा सकता है। ये परिस्थितियाँ हैं: (1) अवकाश से लौटना, (2) भारत के भीतर प्रतिनियुक्ति से मूल विभाग में प्रत्यावर्तन, (3) प्रशिक्षण या विदेशी असाइनमेंट पूरा करने के बाद विदेश से लौटना, (4) भारत के भीतर प्रशिक्षण से लौटना, (5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्देशित पुराने पद पर कार्यभार सौंपने के बाद पदस्थापन की प्रतीक्षा करना, (6) दूसरे पद पर अधिकारी के स्थानांतरण को स्वीकार न करना, और (7) एक सरकारी सेवक के प्रत्यावर्तन को रोकना।

6. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता तर्क देंगे कि यह दावा कि याचिकाकर्ताओं को मनमानी या व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के कारण पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा (APO) के तहत रखा गया था, निराधार है। APO आदेश जनहित में और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार जारी किए गए थे।

6.1. वे तर्क देंगे कि राजस्थान सेवा नियम, 1951 का नियम 25-ए, APO आदेश जारी करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। उसमें उल्लिखित शर्तें उदाहरणात्मक हैं न कि संपूर्ण, और राज्य सरकार जनहित और प्रशासनिक आवश्यकता में ऐसे आदेश जारी करने का अधिकार रखती है।

6.2. वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि स्थानांतरण और पदस्थापन नियमित प्रशासनिक मामले हैं, और कर्मचारियों के पास किसी विशेष स्थान पर तैनात रहने का कोई निहित अधिकार नहीं है। जब तक किसी वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन या स्थापित दुर्भावना न हो, ऐसे प्रशासनिक निर्णय न्यायिक हस्तक्षेप के लिए खुले नहीं हैं। तदनुसार, रिट याचिकाएँ गुण-दोष से रहित हैं और खारिज किए जाने योग्य हैं।

7. मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना है और मामले की पत्रावलियों का अवलोकन किया है। अब मैं आगामी अनुच्छेदों में अपने कारणों और चर्चा को दर्ज करके तर्कों के गुण-दोष पर ध्यान केंद्रित करूँगा।

8. सबसे पहले, मैं यह अवलोकन करना चाहूँगा कि स्थानान्तरण/पदस्थापन, जिसमें एक अधिकारी को APO करना शामिल है, प्रशासनिक आवश्यकता का मामला होने के कारण, यह न्यायालय आम तौर पर हस्तक्षेप करने से परहेज करता है और सावधानी से चलता है, जब तक कि यह कानून के स्पष्ट उल्लंघन या अत्यधिक कठिनाई का मामला न हो। किसी भी दिशानिर्देश या स्थानान्तरण नीति के कथित उल्लंघन, जब तक कि वह अनिवार्य न हो, असाधारण रिट क्षेत्राधिकार के तहत कोई हस्तक्षेप वारंट नहीं करता है, क्योंकि वे आमतौर पर निर्देशात्मक प्रकृति के होते हैं, जो नियोक्ता की प्रशासनिक सुविधा के लिए मानव संसाधन उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए बनाए जाते हैं। इसके अलावा, एक कर्मचारी को स्थानान्तरित करना है या नहीं, यह नियोक्ता का एकमात्र विवेक है और यह एक कर्मचारी की व्यक्तिगत सुविधा के कारण नहीं है। ऐसे आदेशों को सजा या पदोन्नति के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। बल्कि, स्थानान्तरण/पदस्थापन एक सरकारी कर्मचारी की सेवा शर्तों का एक अभिन्न अंग है।

8.1. वास्तव में, विचाराधीन कुछ मामलों में, इस न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम सुरक्षा की अवधि को देखते हुए, इसकी उपयोगिता समय के साथ कम हो गई प्रतीत होती है।

8.2. साथ ही, यह न्यायालय इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं है कि कई मामलों में, याचिकाकर्ताओं ने अपनी संबंधित व्यक्तिगत कठिनाइयों और/या इन आरोपों का उल्लेख किया है कि या तो उन्हें समतुल्य पदस्थापन का दर्जा नहीं दिया गया है या स्थानान्तरण की आड़ में, उनके पदानुक्रम में कमी के आधार पर दंडात्मक उपचार दिया जा रहा है और इस प्रकार अपमान हो रहा है या कुछ मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप और दुर्भावना के आरोप भी हैं। लागू कानून के प्रावधानों के संबंध में आगामी पैरा में बताए गए कारणों और चर्चा के लिए उन मामलों के गुण-दोषों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

9. अब राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 25 ए के प्रासंगिक प्रावधानों की वैधता पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो सक्षम प्राधिकारी को APO आदेश जारी करने में सक्षम बनाता है, स्थिति दिन के उजाले की तरह स्पष्ट प्रतीत होती है। यह पिछले कुछ दशकों से समय की कसौटी पर खरा उतरा है। मूल सेवा नियम बहुत पहले 1951 में

का अर्थ है एक सरकारी सेवक का एक मुख्यालय स्टेशन, जहाँ वह कार्यरत है, से दूसरे ऐसे स्टेशन पर आवागमन, या तो-

- (a) एक नए पद के कर्तव्यों को संभालने के लिए, या
(b) अपने मुख्यालय के परिवर्तन के परिणामस्वरूप।”

11. यहाँ विवाद में जो विचारणीय है, वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा 'पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा' (इसके बाद संक्षेप में 'APO' कहा जाएगा) की श्रेणी में यहाँ व्यथित याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को रखने के लिए लागू की गई प्रशासनिक शक्ति है। राजस्थान सेवा नियम, 1951 में नियम 25 ए के डाले जाने तक 'पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा' श्रेणी का प्रावधान इस प्रकार मौजूद नहीं था, जो दिनांक 14.09.1981 को अधिसूचना के माध्यम से डाला गया था। तब तक, यह दिनांक 07.05.1974 के एक परिपत्र के माध्यम से विकसित प्रशासनिक सरलता का एक उपाय था, जिसमें 'APO' शब्द गढ़ा गया था। यह इस प्रकार है:-

“स्पष्टीकरण

वित्त विभाग अधिसूचना संख्या F.I(18)FD(Gr.2)/74 दिनांक 07.05.1974 पर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके तहत सरकार के प्रशासनिक विभागों को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा की अवधि के दौरान एक सरकारी सेवक को ड्यूटी पर मानने के आदेश जारी करने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई थी बशर्ते कि पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा की अवधि 30 दिनों से अधिक न हो।

यह देखा गया है कि अधिकारियों को लंबे समय तक पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा के तहत रखा जाता है और ऐसे मामले, जिनमें अवधि 30 दिनों से अधिक हो जाती है और इस प्रकार वित्त विभाग से नियमितीकरण की आवश्यकता होती है, भी काफी बार होते हैं। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि 'पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा' की अवधि के लिए अधिकारियों के वेतन और भत्तों पर अनावश्यक व्यय पर लेखा परीक्षा रिपोर्टों में प्रतिकूल टिप्पणी की जाती है; और यह आवश्यक है कि ऐसे व्यय से बचने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

इसलिए, सभी संबंधितों से अनुरोध है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे मामले जिनमें अधिकारियों को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, न हों और यदि ऐसे मामले, कभी-कभी, पूरी तरह से अपरिहार्य होते हैं, तो पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा की अवधि को न्यूनतम रखा जाए। यह भी इसके द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि अब से यह विभाग ऐसे मामलों के नियमितीकरण के लिए तब तक सहमत नहीं होगा जब तक कि किसी अधिकारी को गैर-पदस्थापित करने के लिए ठोस कारण मौजूद न हों।”

(जोर दिया गया)

12. यह 1981 में था कि दिनांक 14.09.1981 की एक अधिसूचना के माध्यम से, राजस्थान सेवा नियम, 1951 में नियम 25-ए डाला गया था, जो इस प्रकार है:

"25 ए. पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा के दौरान वेतन :-

एक सरकारी सेवक जिसे नियम 7 (8) (बी) (iii) के नीचे नोट के तहत अनिवार्य रूप से 'पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा' के तहत रखा जाता है, वह उस दर पर वेतन और भत्तों का हकदार होगा जिस पर वह पुराने पद में कार्यभार छोड़ने से ठीक पहले आहरित कर रहा था। उसे पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा की अवधि के दौरान परिवहन भत्ता या स्थायी यात्रा भत्ता की अनुमति नहीं दी जाएगी।

राजस्थान सरकार का निर्णय

1. सरकारी सेवकों को आमतौर पर निम्नलिखित परिस्थितियों में अनिवार्य रूप से पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा के तहत रखा जाता है:-

- (1) अवकाश से लौटने पर।
- (2) भारत के भीतर प्रतिनियुक्ति से मूल विभाग में प्रत्यावर्तन पर।
- (3) प्रशिक्षण या विदेशी असाइनमेंट पूरा करने के बाद विदेश से लौटने पर।
- (4) भारत के भीतर प्रशिक्षण से लौटने पर।
- (5) नियुक्ति प्राधिकारी के निर्देशों के तहत पुराने पद का कार्यभार सौंपने के बाद पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा करना।
- (6) दूसरे पद पर अधिकारी के स्थानांतरण को स्वीकार न करना।
- (7) एक सरकारी सेवक को प्रत्यावर्तन से बचाने के लिए।

2. एक सरकारी सेवक जो अवकाश पर जाता है, वह औपचारिक पदस्थापन आदेश के अभाव में अवकाश से लौटने पर उस पद पर ड्यूटी फिर से शुरू नहीं कर सकता जिस पर वह अवकाश पर जाने से पहले था। ऐसे मामलों में जहाँ अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी और नियुक्ति प्राधिकारी एक ही है, अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को अवकाश स्वीकृत करने वाले आदेश में अपरिवर्तनीय रूप से यह इंगित करना चाहिए कि अधिकारी को अवकाश की समाप्ति पर उसी पद पर पुनः पदस्थापित किया जाता है। अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी उसी पद पर पुनः पदस्थापन के आदेश भी जारी कर सकता है यदि अवकाश के दौरान पद रिक्त रखा गया था। जहाँ अवकाश नियुक्ति प्राधिकारी के अलावा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशों के तहत अवकाश रिक्ति को भर दिया गया है, तो बाद वाला प्राधिकारी ही अवकाश से लौटने वाले अधिकारी के पुनः पदस्थापन आदेश जारी कर सकता है। ऐसे मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी को सरकारी सेवक के अवकाश की समाप्ति से पहले जितना संभव हो सके पदस्थापन आदेश जारी करने चाहिए ताकि अवकाश से लौटने पर एक सरकारी सेवक को पदस्थापन आदेशों के तहत रखने की आकस्मिकता उत्पन्न न हो।

3. पैरा 1 में आइटम संख्या 2, 3, और 4 पर उल्लिखित परिस्थितियों में रखे गए सरकारी सेवकों के मामले में, सक्षम प्राधिकारी को सरकारी सेवक के प्रतिनियुक्ति/प्रशिक्षण या विदेशी असाइनमेंट से लौटने से कम से कम 15 दिन पहले अपरिवर्तनीय रूप से पदस्थापन के आदेश जारी करने

चाहिए ताकि एक सरकारी सेवक को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा के तहत रखने को समाप्त किया जा सके। इस संबंध में स्थिति की निगरानी और प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के दृष्टिकोण से, एक अधिकारी को प्रतिनियुक्ति, प्रशिक्षण या विदेशी असाइनमेंट पर भेजने के लिए सक्षम प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए रजिस्टर बनाए रखना चाहिए कि भारत के भीतर प्रतिनियुक्ति से या प्रशिक्षण के विदेशी असाइनमेंट शर्तों पर विदेश से लौटने वाले सरकारी सेवकों के पदस्थापन के लिए प्रस्ताव समय पर पदस्थापन आदेश जारी करने के लिए आगे बढ़ाए जाएँ।

4. कभी-कभी सरकारी सेवकों को पद का कार्यभार सौंपने और नियुक्ति प्राधिकारी के निर्देश के तहत पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति से जहाँ तक संभव हो, बचा जाना चाहिए, और यदि कुछ मामलों में यह नितांत आवश्यक है, तो पदस्थापन के आदेश एक सप्ताह के भीतर जारी किए जाने चाहिए। एक रिक्त पद के खिलाफ एक अधिकारी की पदोन्नति के मामले में, पदस्थापन आदेश अपरिवर्तनीय रूप से एक साथ जारी किए जाने चाहिए।

5. एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरित सरकारी सेवकों को पद का कार्यभार संभालने से रोका नहीं जाना चाहिए और उनके पदस्थापन/स्थानांतरण के परिणामस्वरूप ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने वाले अधिकारी को स्वीकार न करने की प्रथा, जो एक अस्वस्थ प्रथा है, से ईमानदारी से बचा जाना चाहिए।

6. सरकारी सेवकों को कभी-कभी निम्नलिखित परिस्थितियों में पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा के तहत रखा जाता है:—

(1) विभागीय पदोन्नति समिति/राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन या नियमितीकरण लंबित होने पर एक सरकारी सेवक का उसके द्वारा अस्थायी क्षमता में रखे गए निचले पद पर प्रत्यावर्तन।

(2) उसके द्वारा रखे गए पद के उन्मूलन के परिणामस्वरूप निचले पद पर प्रत्यावर्तन।

7. यह नियमों की भावना के विरुद्ध है कि एक सरकारी सेवक को तब तक पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में माना जाए जब तक कि उसे रिक्ति होने पर या अन्यथा उसी समय-मान के समान पद पर पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में एक सरकारी सेवक को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में नहीं माना जाएगा, और वह राजस्थान सेवा नियम के नियम 25 ए के तहत वेतन और भत्तों का हकदार नहीं होगा। एक सरकारी सेवक को प्रत्यावर्तित करने वाले प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशों को लागू किया जाना चाहिए। एक सरकारी सेवक को आदेश जारी करने की तारीख से या आदेश में निर्दिष्ट तारीख से, जैसा भी मामला हो, प्रत्यावर्तित माना जाएगा और उसका प्रत्यावर्तन उस तारीख से प्रभावी हो जाता है, भले ही वह प्रत्यावर्तन के तुरंत बाद अवकाश पर जाए या नहीं। ऐसे मामलों में भले ही एक सरकारी सेवक को कैडर में उससे किसी अन्य कनिष्ठ व्यक्ति के प्रत्यावर्तन से बचाने के लिए पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा के तहत रखा जाता है; ऐसी परिस्थितियों में व्यतीत किए गए समय को देय और स्वीकार्य

अवकाश प्रदान करके नियमित किया जाएगा क्योंकि किसी भी परिस्थिति में इसे पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा नहीं माना जाएगा।

8. मौजूदा प्रत्यायोजन के तहत सरकार के प्रशासनिक विभाग के पास एक सरकारी सेवक को 30 दिनों से अधिक न होने वाली अवधि के लिए पदस्थापन आदेशों के तहत रखने की शक्ति है, और 30 दिनों से अधिक की अवधि वाले मामलों में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता होती है। बिना किसी औचित्य के एक सरकारी सेवक को अनावश्यक रूप से लंबी अवधि के लिए पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा के तहत रखना व्यर्थ व्यय शामिल करता है क्योंकि सरकारी सेवक पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा के दौरान निष्क्रिय रहता है। इसलिए, सभी संबंधित प्राधिकारियों से अनुरोध है कि पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा के मामलों को समाप्त करने और इस प्रकार व्यर्थ व्यय से बचने के दृष्टिकोण से इन निर्देशों का ईमानदारी से पालन करें। पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा के प्रत्येक मामले की, जिसमें एक सरकारी सेवक को पर्याप्त कारणों और औचित्य के बिना अनावश्यक रूप से लंबी अवधि के लिए पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा के तहत रखा गया है, प्रशासनिक विभाग द्वारा पहले अपने स्तर पर जांच की जानी चाहिए और इन निर्देशों या सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किए गए किसी अन्य निर्देश के उल्लंघन में पदस्थापन आदेश जारी करने में देरी के लिए जिम्मेदार दोषी सरकारी सेवक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।”

(जोर दिया गया)

उपरोक्त वैधानिक योग के माध्यम से, 1981 में नियम 25-ए के माध्यम से पहली बार एक सरकारी सेवक को अनिवार्य रूप से 'पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा' के तहत रखा जाना अनिवार्य किया गया था।

12.1. राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 25-ए में बाद में 02.07.2024 को एक संशोधन किया गया था, जो इस प्रकार है:

Xx xx xx

“2. नियम 25 ए का संशोधन।-

राजस्थान सेवा नियम, 1951 का मौजूदा नियम 25 ए, जिसमें 'राजस्थान सरकार का निर्णय' और उसके तहत दिखाई देने वाले 'राजस्थान सरकार के निर्देश' शामिल नहीं हैं, को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्।-

25 ए. पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा के दौरान वेतन।-

एक सरकारी सेवक जिसे नियम 7(8)(बी)(iii) के नीचे नोट के तहत अनिवार्य रूप से पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा के तहत रखा जाता है, वह उस दर पर वेतन और भत्तों का हकदार होगा जिस पर वह पुराने पद का कार्यभार छोड़ने से ठीक पहले आहरित कर रहा था।

उसे पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा की अवधि के दौरान परिवहन भत्ता या स्थायी यात्रा भत्ता की अनुमति नहीं दी जाएगी।

परंतु जहाँ एक सरकारी सेवक को एक विशेष स्थान पर पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा के तहत रखा जाता है, वह गृह किराया भत्ता नियम, 1989 और प्रतिपूरक (नगर) भत्ता नियम के नियमों और शर्तों के अनुसार उस विशेष स्थान के गृह किराया भत्ता और प्रतिपूरक (नगर) भत्ता का हकदार होगा।”

12.2. चूंकि कई याचिकाकर्ताओं द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले इस स्तर पर इसे भी देखा जा सकता है। यह इस प्रकार है:-

“13. निलंबन (*Suspension*):-

1. नियुक्ति प्राधिकारी या कोई भी प्राधिकारी जिसके वह अधीनस्थ है या सरकार द्वारा इस संबंध में सशक्त कोई अन्य प्राधिकारी एक सरकारी सेवक को निलंबित कर सकता है।

(a) जहाँ उसके खिलाफ एक अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है या लंबित है, या

(b) जहाँ उसके खिलाफ किसी आपराधिक अपराध के संबंध में एक मामला जांच या परीक्षण के अधीन है:

परंतु जहाँ निलंबन का आदेश नियुक्ति प्राधिकारी से निम्न प्राधिकारी द्वारा किया जाता है, तो ऐसा प्राधिकारी उस परिस्थिति की सूचना तत्काल नियुक्ति प्राधिकारी को देगा जिसमें आदेश किया गया था।

2. एक सरकारी सेवक जिसे अड़तालीस घंटे से अधिक की अवधि के लिए, चाहे वह आपराधिक आरोप पर हो या अन्यथा, हिरासत में लिया जाता है, उसे उप-नियम (1) के तहत एक सरकारी सेवक को निलंबित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश से हिरासत की तारीख से निलंबित माना जाएगा और अगले आदेशों तक निलंबित रहेगा।

3. जहाँ निलंबन के अधीन एक सरकारी सेवक पर लगाए गए सेवा से बर्खास्तगी, निष्कासन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा को इन नियमों के तहत अपील या पुनरीक्षण में अलग कर दिया जाता है और मामले को आगे की जांच या कार्रवाई के लिए या किसी अन्य निर्देश के साथ वापस भेज दिया जाता है, तो उसके निलंबन का आदेश मूल बर्खास्तगी, निष्कासन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश की तारीख से और तब से लागू माना जाएगा और अगले आदेशों तक लागू रहेगा।

4. जहाँ एक सरकारी सेवक पर लगाई गई सेवा से बर्खास्तगी, निष्कासन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा को कानून की अदालत के निर्णय के परिणामस्वरूप या द्वारा अलग कर दिया जाता है या शून्य घोषित कर दिया जाता है और अनुशासनात्मक प्राधिकारी, मामले की परिस्थितियों पर विचार करने पर, उन आरोपों पर उसके खिलाफ आगे की जांच करने का निर्णय लेता है जिनमें मूल रूप से बर्खास्तगी, निष्कासन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा लगाई गई थी, तो सरकारी सेवक को मूल बर्खास्तगी, निष्कासन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश की तारीख से नियुक्ति

प्राधिकारी द्वारा निलंबित माना जाएगा और अगले आदेशों तक निलंबित रहेगा।

5. इस नियम के तहत किए गए या किए गए माने जाने वाले निलंबन के किसी भी आदेश को उस प्राधिकारी द्वारा जिसे आदेश किया गया था या जिसे आदेश किया गया माना जाता है या उस प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी भी प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।”

13. उपरोक्त कानूनी स्थिति के आलोक में, दो प्रासंगिक प्रश्न जो इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आवश्यक रूप से उत्पन्न होते हैं, वे हैं:

A. क्या नियम 7(8)(b)(iii) सहपठित राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 25-ए, को उन मामलों में लागू किया जा सकता है जहाँ जनहित में यह महसूस किया जाता है कि एक अधिकारी को निलंबित करने के बजाय, अगला निर्णय लिए जाने तक उसे 'पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा' की श्रेणी में रखकर केवल काम वापस लेकर अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाए?

B. क्या एक कर्मचारी/अधिकारी की सेवाओं को 'पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा' श्रेणी के तहत रखना केवल 'स्थानांतरण' का आदेश पारित करने से बचने के लिए एक विनम्र शब्द है और/या राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम-13 की कठोरताओं को दूर करने के लिए एक बहाना है और/या स्थानांतरण आदेशों पर लगाए गए प्रतिबंध को धता बताने के लिए, जो समय-समय पर लगाया जा सकता है/लगाया जाता है?

14. आइए हम पहले प्रश्न 'बी' से निपटते हैं। यहाँ विचाराधीन याचिकाओं के पूरे समूह के सभी मामलों में, यह पता चलता है कि अधिकारियों की दो श्रेणियों में से कोई एक मौजूद है; अर्थात्:-

- (i) यहाँ उन्हें मुख्यालय बदले बिना उन्हें पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा श्रेणी के तहत रखकर कोई कर्तव्य नहीं सौंपा गया है;
- (ii) यहाँ कर्मचारियों को न केवल कोई कर्तव्य सौंपा गया है, बल्कि साथ ही उनका मुख्यालय भी बदल दिया गया है।

15. जब बाद की श्रेणी (ii) में एक प्रशासनिक आदेश, 1951 के नियमों के नियम 7(38) में निहित स्थानांतरण की परिभाषा पर परखा जाता है, तो यह संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है कि यह स्थानांतरण के समान है। ऐसे मामलों में, 'पदस्थापन

आदेशों की प्रतीक्षा' शब्द का मात्र उपयोग APO की आड़ में एक अधिकारी के स्थानान्तरण के दायरे से आदेश को बाहर नहीं करेगा। तदनुसार, ऐसे कार्य नियम निर्माताओं द्वारा परिकल्पित विधायी मापदंडों पर कायम नहीं रह सकते हैं। ऐसे सहारा को अस्वीकृत करने के लिए ही नोट किया जा रहा है।

उस श्रेणी पर आगे बढ़ते हुए जहाँ मुख्यालय नहीं बदले गए हैं, वे स्थानान्तरण की परिभाषा के दायरे से बाहर प्रतीत होते हैं। इसलिए, ऐसे मामलों में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रशासनिक प्राधिकारी आगे का निर्णय लिए जाने तक ऐसे अधिकारी को वास्तव में स्थानान्तरित करने के लिए APO के आदेश पारित करने के लिए पूरी तरह से न्यायोचित होगा। प्रश्न 'बी' का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।

16. अब प्रश्न 'ए' पर आते हैं [क्या, नियम 7(8)(b)(iii) सहपठित राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 25-ए, को, उन मामलों में लागू किया जा सकता है जहाँ जनहित में यह महसूस किया जाता है कि एक अधिकारी को निलंबित करने के बजाय, आगे का निर्णय लिए जाने तक उसे 'पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा' की श्रेणी में डालकर केवल काम वापस लेकर अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाए? यह पता चलता है कि यह अब विवाद का विषय नहीं है। प्रश्न 'ए' का उत्तर पहले ही इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा **सुकुमार कश्यप बनाम राजस्थान राज्य¹** मामले में दिए गए निर्णय में नकारात्मक में दिया जा चुका है। मैं इस स्तर पर, मेरे विद्वान भाई अरुण भंसाली, जे. (जैसा कि वह तब इस न्यायालय में थे) द्वारा दिए गए अवलोकनों को लाभप्रद रूप से उद्धृत कर सकता हूँ, जो इस प्रकार हैं:

“मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए प्रस्तुतियों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है। यह निस्संदेह सच है कि नियम, 1951 के नियम 25 ए के प्रावधान केवल 'APO के दौरान वेतन' से संबंधित हैं और किसी भी मूल प्रावधान/मापदंड को इंगित नहीं करते हैं जिसके लिए एक अधिकारी को APO रखा जा सकता है। हालाँकि, नियम, 1951 के नियम 25 ए के तहत राजस्थान सरकार के निर्णयों ने सरकारी सेवकों को APO रखने की प्रथा से विस्तार से निपटा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पिछले निर्देशों का उल्लेख किया गया है और इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रशासनिक विभाग को APO के तहत सरकारी कर्मचारियों को एक नियमित के रूप में या अनुशासनात्मक कार्रवाई के विकल्प के रूप में रखने से बचना चाहिए, इसके अलावा उन परिस्थितियों को भी इंगित किया गया है जिनमें आदेश पारित किए जा सकते हैं। इंगित की गई परिस्थितियाँ अनिवार्य रूप से उन मामलों से संबंधित हैं जहाँ एक कर्मचारी, जो अवकाश, प्रतिनियुक्ति पर था,

1 एस.बी. सिविल रिट याचिका सं. 7010/2020 निर्णय दिनांक 14.10.2020

विदेश गया था, प्रशिक्षण पर था, आदि, वापस कार्यग्रहण करनेपर, APO रखा जा सकता है।

विद्वान एएजी विशिष्ट प्रश्न के बावजूद, एक सरकारी सेवक को 'APO' रखने से संबंधित किसी भी मूल प्रावधान को इंगित करने में विफल रहे। जवाब में और उत्पादित नोट शीट में पूरा जोर कथित कदाचार से संबंधित याचिकाकर्ता के खिलाफ विभिन्न आरोपों और इस तथ्य पर है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसकी जाँच की जा रही थी और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जाँच निष्पक्ष हो, उसे APO रखा जा रहा था।

जैसा कि यहाँ पहले ही ध्यान दिया गया है, नियम, 1951 के नियम 25 ए के तहत निर्देशों ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के विकल्प के रूप में एक अधिकारी को APO रखने की प्रथा का संज्ञान लिया है और उस प्रथा की निंदा की है। इसके अलावा, यह सुस्थापित है कि स्थानांतरण जैसे किसी अन्य आदेश को पारित करने और/या APO रखने की आड़ में एक सरकारी सेवक के खिलाफ सजा की प्रकृति में कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इसे देखते हुए, याचिकाकर्ता के कथित आचरण के कारण आदेश पारित किए जाने के संबंध में प्रत्यर्थियों की विशिष्ट स्वीकृति के आधार पर, याचिकाकर्ता को APO रखने के प्रत्यर्थियों के कार्य को कायम नहीं रखा जा सकता है।

जहाँ तक यह प्रस्तुतियाँ हैं कि याचिकाकर्ता का आचरण ऐसा है कि वह वर्तमान पदस्थापन के स्थान पर बने रहने का हकदार नहीं है, यदि प्रत्यर्थी याचिकाकर्ता के आचरण को इतना आपत्तिजनक पाते हैं, तो वे विभिन्न सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही कर सकते हैं और एक अधिकारी को APO रखने की प्रथा को ऐसे कार्य के विकल्प के रूप में सहारा नहीं लिया जा सकता है।

प्रत्यर्थी नियुक्ति प्राधिकारी / अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए हमेशा स्वतंत्र हैं, यदि आवश्यक समझा जाए।

फलस्वरूप, याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थियों द्वारा पारित दिनांक 7/8/2020 का आदेश (अनुलग्नक 3) याचिकाकर्ता के संबंध में रद्द और अपास्त किया जाता है। हालाँकि, प्रत्यर्थी कानून के अनुसार आवश्यक समझे जाने पर याचिकाकर्ता के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।”

17. उपरोक्त स्थिति को वास्तव में **डॉ. महेश कुमार पंवार बनाम राजस्थान राज्य²** में दिए गए एक अन्य समन्वय पीठ के निर्णय के माध्यम से आगे स्पष्ट किया गया था, जिसमें इस न्यायालय के लिए बोलते हुए, मेरे विद्वान भाई विनीत कुमार माथुर, जे. ने निम्नानुसार अवलोकन किया:

“इस न्यायालय की राय में, निर्णय केवल उदाहरणत्मक हैं और वे समावेशी नहीं हो सकते हैं, इसलिए, नियम 25 ए और राजस्थान सरकार के निर्णयों से जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है वह यह है कि पदस्थापन

आदेश की प्रतीक्षा को स्थानांतरण आदेश के प्रतिस्थापन के रूप में नियमित मामले के रूप में नहीं बल्कि केवल कुछ आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए आमतौर पर पारित किया जाना चाहिए। पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा का उपयोग कुछ व्यक्तियों के समायोजन/सुविधाके लिए स्थानांतरण के आदेशों को दरकिनार करने के एक उपकरण के रूप में नहीं किया जा सकता है।

APO का आदेश किसी व्यक्ति को दंडित करने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई के स्थान पर उपयोग नहीं किया जा सकता है। यदि किसी सरकारी सेवक ने कोई गलती की है तो उस व्यक्ति के खिलाफ नियमों के अनुसार उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है और इसलिए, ऐसे मामलों में पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा पारित करना टिकाऊ नहीं है।

राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने नियम 25 ए के तहत राजस्थान सरकार के निर्णय के निर्णय संख्या 5 के दायरे में लाकर पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा को न्यायोचित ठहराने की कोशिश की है, लेकिन इस न्यायालय की राय में, वर्तमान मामला 1951 के नियमों के नियम 25 ए के तहत राज्य सरकार के निर्णय संख्या 5 के तहत दूर से भी शामिल नहीं है।

इसलिए, यह न्यायालय दृढ़ता से इस मत का है कि पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा को एक अनैच्छिक और यांत्रिक तरीके से पारित नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। राज्य के पदाधिकारियों द्वारा प्रतिबंध की पवित्रता का पालन किया जाना आवश्यक है।"

18. मैं इन दोनों निर्णयों में लिए गए दृष्टिकोण से विनम्र सहमति में हूँ।
19. राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 7 और 25 ए के संयुक्त पठन से, यह निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि एक APO आदेश पारित करने के लिए, नियम 25 ए में उल्लिखित सात आकस्मिकताएँ उदाहरणत्मक हैं न कि समावेशी। हालाँकि, इसकी व्याख्या इस अर्थ में नहीं की जानी चाहिए कि नियम 25 ए का उपयोग नियम 13 में निहित सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने के लिए किया जा सकता है, जो निलंबन को केवल कुछ विशिष्ट शर्तों के तहत प्रतिबंधित करता है। यदि एक APO आदेश बिना किसी वैध आकस्मिकता को बताए जारी किया जाता है — या यदि disclosed कारण नियम 13 का उल्लंघन करता है — तो यह प्रशासनिक आवश्यकता की आड़ में, विधायी इरादे का उल्लंघन है। ऐसा पाठ्यक्रम कानून के तहत स्पष्ट रूप से अनुमेय नहीं है। तदनुसार, जब भी नियम 7(8)(b)(iii) के तहत शक्ति को नियम 25 ए के संयोजन में लागू किया जाता है, तो प्रशासनिक प्राधिकारी को नियम में निर्दिष्ट सात आकस्मिकताओं से परे आकस्मिकताओं को लागू करने के लिए कारण स्पष्ट रूप से बताने चाहिए। इस प्रकार, सभी मामलों में, प्रशासनिक प्राधिकारी को पदस्थापन आदेश की

प्रतीक्षा के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना चाहिए — चाहे वह गिनती की गई आकस्मिकताओं के भीतर आता हो या प्रशासनिक आवश्यकता से उत्पन्न होता हो।

19.1. नियम 7(8)(b)(iii) और 25 ए की व्याख्या करते समय, (समान श्रेणी का) का सिद्धांत आवश्यक रूप से लागू होगा और इस प्रकार अन्य गैर-समावेशी परिस्थितियों में समान संज्ञानात्मक अर्थ होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कानून का एक प्रावधान "कार, ट्रक, मोटरसाइकिल, और अन्य वाहन" को संदर्भित करता है, तो वाक्यांश "अन्य वाहन" की व्याख्या केवल समान परिवहन माध्यमों (जैसे, बसें, वैन) को शामिल करने के लिए की जाएगी, न कि हवाई जहाजों या नावों को। जब हम नियम 25 ए पर (समान तत्त्व) *Ejusdem Generis* लागू करते हैं, तो यह पता चलता है कि नियम उन विशिष्ट परिस्थितियों की एक सूची प्रदान करता है जहाँ यह लागू होता है, जैसे: अवकाश से लौटना; भारत के भीतर प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावर्तन; प्रशिक्षण या विदेशी असाइनमेंट पूरा करना; भारत के भीतर प्रशिक्षण से लौटना या नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशों के तहत पिछले पद का कार्यभार सौंपना और नए पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा करना। नियम 7(8)(b) विशेष रूप से प्रदान करता है कि सरकार यह घोषित करने वाले आदेश जारी कर सकती है कि उसमें निर्दिष्ट परिस्थितियों में, या उससे मिलती-जुलती परिस्थितियों में, एक सरकारी सेवक को ड्यूटी पर माना जा सकता है। यह इंगित करता है कि नियम "अन्य समान स्थितियों" पर लागू होता है जहाँ एक कर्मचारी पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा कर रहा है। वाक्यांश "अन्य समान स्थितियाँ" की व्याख्या सूचीबद्ध परिस्थितियों के समान श्रेणी में की जानी चाहिए।

19.2. परिणामस्वरूप, नियम 7(8)(b) या 25 ए, उक्त, किसी भी विचाराधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई, निलंबन, या उन मामलों पर लागू नहीं होते हैं जहाँ दंडात्मक उपाय के रूप में पदस्थापन को जानबूझकर रोका जाता है। नियम 7(8)(b) और नियम 25 ए केवल उन कर्मचारियों पर लागू हो सकते हैं जो उसमें निर्दिष्ट आकस्मिकताओं (जैसे स्थानान्तरण, प्रत्यावर्तन, या प्रशिक्षण से वापसी) या अन्य समान आकस्मिकताओं के कारण पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसे उन स्थितियों को कवर करने के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है जहाँ या तो अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का प्रस्ताव है या एक अधिकारी को एक जाँच लंबित होने तक निलंबित किया जाना है या "पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा" की आड़ में एक पद से विचाराधीन निष्कासन है।

19.3. अनुशासनात्मक कार्यवाही को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत निपटाया जाना चाहिए, न कि राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 25 ए के तहत। इस प्रकार, नियम 25 ए को अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं से बचने के साधन के रूप में लागू नहीं किया जाना चाहिए। यदि एक प्रशासनिक प्राधिकारी दंडात्मक कारणों से पदस्थापनों में देरी के लिए नियम 25 ए का दुरुपयोग करता है, तो ऐसा कार्य कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं होगा।

19.4. इसलिए, मेरा मत है कि राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 25 ए को राजस्थान सी.सी.ए. नियम, 1958 के नियम 13 को दरकिनार करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। कारण स्पष्ट हैं। नियम 13 (राजस्थान सी.सी.ए. नियम, 1958) अनुशासनात्मक कार्यवाही को नियंत्रित करता है और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए उचित प्राधिकारी और प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है। जबकि, नियम 25 ए (राजस्थान सेवा नियम, 1951) केवल वेतन और भत्तों से संबंधित है जब एक कर्मचारी पिछले पद से कार्यमुक्त होने के बाद नए पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहा होता है। चूंकि नियम 25 ए अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए लागू नहीं है, इसलिए इसका उपयोग नियम 13 के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने या बायपास करने के लिए नहीं किया जा सकता है। यदि किसी कर्मचारी पर कदाचार, अक्षमता, या अन्य दोष का आरोप है जो अनुशासनात्मक कार्यवाही को वारंट करता है, तो प्रक्रियात्मक निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 13 का पालन किया जाना चाहिए।

19.5. संक्षेप में, राजस्थान सेवा नियम, 1951 का नियम 25 ए विशुद्ध रूप से वेतन निरंतरता के लिए एक प्रशासनिक प्रावधान है — यह अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है। राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 का नियम 13 अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए लागू है — इसे नियम 25 ए के माध्यम से बायपास करना अवैध होगा। यदि किसी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के तहत औपचारिक अनुशासनात्मक कार्यवाही के बिना एक विस्तारित अवधि के लिए "पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा" में रखा जा रहा है, तो यह शक्ति के दुर्भावनापूर्ण प्रयोग के समान होगा। इसके अलावा, शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए, उन मामलों में जहाँ या तो नियम 7(8) और/या नियम 25-ए के तहत आकस्मिकताओं का खुलासा नहीं किया गया है और/या यदि खुलासा किया गया है, तो वे उससे मिलती-जुलती

आकस्मिकताओं के अलावा अन्य हैं, APO आदेश उन नियमों का उल्लंघन कर रहे होंगे। ऐसा कार्य कानून में स्पष्ट रूप से अनुमेय नहीं है।

20. तदनुसार, यह माना जाता है कि एक APO का आदेश केवल राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 7(8)(b)(iii) और/या नियम 25-ए में निर्दिष्ट आकस्मिकताओं में या अन्य समान आकस्मिकताओं में पारित किया जा सकता है। इसके अलावा, सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी संबंधित कर्मचारी को प्रासंगिक लागू आकस्मिकता को रिकॉर्ड करने और सूचित करने के लिए बाध्य होगा। संबंधित कर्मचारी को प्रासंगिक लागू आकस्मिकता को रिकॉर्ड करने और सूचित करने में विफलता उक्त नियम 7(8)(b)(iii) को नियम 25-ए के साथ पढ़े जाने पर उसके इरादे, पत्र और भावना का उल्लंघन होगा और कपटी और दुर्भावनापूर्ण शक्ति के प्रयोग की बू आएगी।

21. समाप्त करने से पहले, मैं यह शीघ्रता से जोड़ सकता हूँ कि प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **पुष्कर लाल माली बनाम राजस्थान राज्य** ³में दिए गए खंडपीठ के निर्णय के एक अप्रासंगिक कथन पर रखा गया भरोसा थोड़ा संदर्भ से बाहर लगता है। इसके अलावा, यह अवलोकन कि नियम 25 में दिए गए आकस्मिकताएँ समावेशी नहीं हैं, अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित मामले पर चुपचाप किया गया था, न तो किसी विशिष्ट तर्क को संबोधित करते हुए और न ही मुद्दे पर सीधे चर्चा करते हुए, प्रभावी रूप से इसे औपचारिक तर्क के बिना मान लिया गया। दोहराव की कीमत पर, एक प्रशासनिक प्राधिकारी को सामान्य रूप से नियम 25-ए के तहत प्रदान की गई आकस्मिकताओं के दायरे से परे नहीं जाना चाहिए। उक्त अप्रासंगिक कथन से बल प्राप्त करके, इस तर्क को स्वीकार करना कि उन सभी मामलों में जिन्हें 'असामान्य' कहा जा सकता है और इसलिए नियम 13 को शीघ्रता से निपटाया जा सकता है, न्याय का उपहास होगा और सेवा न्यायशास्त्र की पूरी योजना की गलत व्याख्या भी होगी। नियम 13 को अग्रता मिलनी चाहिए क्योंकि यह नियम 25-ए की तुलना में अधिक मजबूत आधार पर खड़ा है। आवश्यक रूप से, इसलिए, एक परिणाम के रूप में, जहाँ पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा के कारण विचाराधीन विभागीय जाँच हैं, ऐसे प्रशासनिक आदेश कायम नहीं रह सकते हैं।

22. निष्कर्ष निकालते हुए, भविष्य में अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के लिए, राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 25-ए को लागू करने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों को तैयार करना उपयुक्त समझा जाता है:

पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा (APO) पर दिशानिर्देश

1. APO का उद्देश्य और औचित्य:

- (i). इसे प्रशासनिक आवश्यकता या जनहित के आधार पर जारी किया जाना चाहिए, न कि दंडात्मक उपाय के रूप में।
- (ii). एक कर्मचारी को APO के तहत रखने का कारण स्पष्ट रूप से लिखित में बताया जाना चाहिए।
- (iii). APO का उपयोग अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रतिस्थापन या बहाने के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।

2. APO जारी करने की शर्तें:

2.1. राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 25-ए के तहत 'आमतौर पर' निम्नलिखित परिस्थितियों में पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा पारित की जानी चाहिए:

- (i). अवकाश से लौटना।
- (ii). प्रतिनियुक्ति के बाद मूल विभाग में प्रत्यावर्तन।
- (iii). प्रशिक्षण (घरेलू या विदेशी) से लौटना।
- (iv). पिछले पद से कार्यमुक्त होने के बाद पदस्थापन की प्रतीक्षा करना।
- (v). दूसरे पद पर अधिकारी के स्थानांतरण को स्वीकार न करना।
- (vi). एक सरकारी सेवक के प्रत्यावर्तन को रोकना।

2.2. हालाँकि नियम 25-ए में उल्लिखित शर्तें उदाहरणात्मक हैं, लेकिन लागू करने के लिए प्रस्तावित कोई भी अन्य शर्त समान प्रशासनिक आवश्यकता के साथ संरेखित होनी चाहिए (Ejusdem Generis का सिद्धांत)।

3. सीमाएँ और प्रतिबंध:

- (i). APO का उपयोग राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 13, जो निलंबन को नियंत्रित करता है, को दरकिनार करने के लिए नहीं किया जा सकता है।
- (ii). APO को 30 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए जब तक कि वैध औचित्य के साथ वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित न हो।
- (iii). उचित कारण के बिना लंबे समय तक APO की स्थिति प्राधिकार का दुरुपयोग है।

4. प्रशासनिक जवाबदेही:

- (i). संबंधित कर्मचारी/अधिकारी को APO आदेश का कारण सूचित किया जाना चाहिए।
- (ii). सरकार पर अनावश्यक वित्तीय बोझ को रोकने के लिए भविष्य के पदस्थापन आदेशों को समय पर जारी करना सुनिश्चित करें।
- (iii). APO आदेशों से बचा जाना चाहिए जो वास्तविक निलंबन के समान हैं या विचाराधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई में देरी के साधन के रूप में कार्य करते हैं।

23. राजस्थान राज्य (सभी याचिकाओं में प्रत्यर्थी) को (उसके मुख्य सचिव के माध्यम से) सभी विभाग प्रमुखों/प्रशासनिक सचिवों और अन्य सक्षम प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक प्रशासनिक निर्देश जारी करने का निर्देश दिया जाता है ताकि उन्हें इस न्यायालय द्वारा तैयार किए गए उपरोक्त दिशानिर्देशों और इस तत्काल निर्णय की प्रति के बारे में संवेदनशील बनाया जा सके। इस न्यायालय का रजिस्ट्री इस तत्काल आदेश को ईमेल के माध्यम से राज्य के मुख्य सचिव को उनकी जानकारी और आवश्यक अनुपालन के लिए सूचित करेगा।

24. उपरोक्त दिशानिर्देशों के आलोक में, चूंकि किसी भी याचिकाकर्ता को उनकी सेवाओं को APO श्रेणी के तहत रखने के लिए लिखित में कारण सूचित नहीं किए गए थे (हालांकि बाद में कुछ मामलों में जवाब-प्रस्तुतियों में उनका खुलासा किया गया था),

अनुलग्नक-‘ए’ के अनुसार समूह में सभी चुनौती दिए गए आदेश (APO) उनके संबंध में रद्द किए जाते हैं, जिसके परिणाम भी होंगे। जिन चुनौती दिए गए आदेशों में सूचित किए गए कारण “विचाराधीन या लंबित विभागीय कार्रवाई” या कर्तव्य की उपेक्षा या शिकायत की प्राप्ति हैं या जहाँ भी मुख्यालय बदल दिया गया था जो स्थान/स्थानान्तरण के परिवर्तन के समान था, वे उन अतिरिक्त कारणों से रद्द किए जाने योग्य हैं। तदनुसार ऐसा आदेश दिया जाता है।

25. हालाँकि, यदि प्रशासनिक आवश्यकता इसकी माँग करती है, तो राज्य का सक्षम प्राधिकारी 1951 के नियमों के नियम 25-ए के तहत लिखित में कारणों को सूचित करते हुए, कानून के अनुसार, APO के नए आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा। यह तत्काल आदेश प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं के संबंध में सामान्य रूप से नए स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश पारित करने से भी नहीं रोकेगा।

26. सभी रिट याचिकाएँ उपरोक्त के अनुसार निपटा दी जाती हैं।

27. सभी लंबित आवेदन (ओं) को भी निपटा दिया जाता है।

(अरुण मोंगा), जे.

रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त: हाँ / नहीं

जितेंद्र राणा - सुमित शर्मा

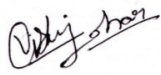
अनुलग्नक-ए					
क्रम सं.	मामला सं.	शीर्षक / पद और विभाग	APO की तिथि	कारण	मुख्यालय बदला गया
1.	10380/2024	सेवाराम बनाम राज्य पंचायती राज विभाग (VDO)	18.06.2024	प्रशासनिक कारण	नहीं
2.	13421/2024	प्रमोद कुलहर बनाम राज्य (ब्याख्याता) शिक्षा विभाग	05.08.2024	दुर्व्यवहार और प्रशासनिक कारण	हाँ
3.	14356/2024	अशोक कुमार पारीक बनाम राज्य (मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी)	24.07.2024	कारण उल्लेख नहीं	हाँ

		विभाग माध्यमिक शिक्षा			
4.	14375/2024	रत्ना कुमारी बनाम राज्य (महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता) चिकित्सा विभाग	23.08.2024	कर्तव्य की उपेक्षा	नहीं
5.	14876/2024	भरत सिंह चौधरी बनाम राज्य (निरीक्षक भूमि राजस्व)	28.08.2024	प्रशासनिक कारण	नहीं
6.	15007/2024	ओम प्रकाश बनाम राज्य (पटवारी) विभाग भू-अभिलेख	02.09.2024	कारण उल्लेख नहीं	नहीं
7.	15029/2024	भूपेंद्र कुमार बनाम राज्य (नर्सिंग अधिकारी) चिकित्सा विभाग	03.09.2024	कर्तव्य की उपेक्षा	हाँ
8.	15366/2024	गनराज विश्वादेई बनाम राज्य (नर्सिंग अधिकारी) चिकित्सा विभाग	03.09.2024	कर्तव्य की उपेक्षा और लंबित जाँच	हाँ
9.	16368/2024	रणजीत सिंह बनाम राज्य (वरिष्ठ शिक्षक विज्ञान) विभाग माध्यमिक शिक्षा	20.09.2024	कारण उल्लेख नहीं	नहीं
10.	16549/2024	भारती सामरिया बनाम राज्य (प्रिंसिपल) शिक्षा विभाग	21.09.2024	छात्रों की शिकायत पर	नहीं
11.	17068/2024	विजय कुमार बनाम राज्य (व्याख्याता ग्रेड-1) विभाग माध्यमिक शिक्षा	09.10.2024	दुर्व्यवहार और अनुशासनहीनता	नहीं
12.	17227/2024	सरोज विश्वादेई बनाम राज्य (प्रिंसिपल) शिक्षा विभाग	09.10.2024	सहकर्मियों के साथ विवाद और भेदभाव	नहीं
13.	17546/2024	गंगाराम बनाम राज्य (जूनियर सहायक) पंचायती राज विभाग	15.10.2024	कारण उल्लेख नहीं	नहीं

14.	17923/2024	गोकुल चंद मीणा बनाम राज्य (निरीक्षक) खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग	29.08.2024	प्रशासनिक कारण	हाँ
15.	18369/2024	राजेश कुमार रामवत बनाम राज्य (VDO) विभाग पंचायत समिति	17.09.2024	एक अन्य VDO की पदस्थापना पर	नहीं
16.	18480/2024	उषा चौधरी बनाम राज्य (निरीक्षक लेखा परीक्षा ग्रेड-I) सहकारिता विभाग	29.10.2024	कारण उल्लेख नहीं	हाँ
17.	19721/2024	लोकेश कुमार फगेरिया बनाम राज्य (जूनियर सहायक) पंचायती राज विभाग	06.11.2024	कारण उल्लेख नहीं	नहीं
18.	20479/2024	पूनम कुमारी बनाम राज्य (VDO) पंचायत समिति	04.12.2024	कारण उल्लेख नहीं	नहीं
19.	20736/2024	सुरेंद्र कुमार पूनिया बनाम राज्य (उप निदेशक) सामाजिक न्याय और अधिकारिता	03.12.2024	कारण उल्लेख नहीं	हाँ
20.	21343/2024	सुमित्रा पंवार बनाम राज्य (उप DEO) शिक्षा विभाग	13.12.2024	प्रतिनियुक्ति रद्द।	हाँ
21.	21405/2024	चित्रेश पटेल बनाम राज्य (VDO) विभाग पंचायत समिति	13.12.2024	कारण उल्लेख नहीं	नहीं
22.	21725/2024	भूरा राम बनाम राज्य (VDO) विभाग पंचायत समिति	14.12.2024	कर्तव्य की उपेक्षा	नहीं

23.	21728/2024	नरेंद्र और अन्य बनाम राज्य (PTI) शिक्षा विभाग	07.12.2024	प्रशासनिक कारण	नहीं
24.	796/2025	जीवन राम बनाम राज्य (ADO) विभाग पंचायत समिति	03.01.2025	कारण उल्लेख नहीं	हाँ
25.	2525/2025	पवन कुमार बनाम राज्य (तहसीलदार) विभाग राजस्व बोर्ड	21.01.2025	कारण उल्लेख नहीं	हाँ
26.	3368/2025	जय प्रकाश पांडिया बनाम राज्य (VDO) विभाग पंचायत समिति	28.01.2025	गृह नगर पंचायत समिति	नहीं
27.	4247/2025	मोहम्मद सलीम बनाम राज्य (शिक्षक स्तर-II) शिक्षा विभाग	07.01.2025	कारण उल्लेख नहीं	नहीं

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़